Indian Journal of
Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

मध्यप्रदेश में 2000 के बाद विद्यालयों में नवीन खेल सुविधाओं का विकास: राज्य खेल नीति के क्रियान्वयन का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन

संजीव कुमार पाण्डेय [1], डॉ० संजीव मिश्रा [2], प्रोफेसर (डॉ.) पवन कुमार पचौरी [3*], डॉ. नीलम श्रीवास्तव [4]
[1] (शारीरिक शिक्षा) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश, भारत
[2] सहा० प्रा० शा०शि० विभाग अ०प्र० सिंह विश्वविद्यालय रीवा, मध्यप्रदेश, भारत
[3] विभागाध्यक्ष शारीरिक शिक्षा एवं योग विभाग कुलभास्कर आश्रम पीजी कालेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत
[4] प्राचार्या वैष्णवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author: * प्रोफेसर (डॉ.) पवन कुमार पचौरी

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20808762

सारांश

वर्तमान शोध पत्र मध्यप्रदेश में वर्ष 2000 के पश्चात् विद्यालयों में खेल सुविधाओं (खेल मैदान, उपकरण, व्यायाम शिक्षक, इनडोर / आउटडोर हॉल तथा अकादमियाँ) के विकास तथा राज्य खेल नीति 2005 के क्रियान्वयन का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों - मध्यप्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की रिपोर्टों, 2005 खेल नीति दस्तावेज, राज्य बजट दस्तावेज (2025-26 एवं 2026-27), खेलो इंडिया रिपोर्ट तथा उपलब्ध अकादमिक अध्ययनों पर आधारित है। मुख्य निष्कर्ष यह है कि 2005 की राज्य खेल नीति ने स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 40 मिनट का अनिवार्य खेल पीरियड, नये स्कूलों में खेल मैदान की अनिवार्यता तथा व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की। इससे ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में भी खेल सुविधाओं का विस्तार हुआ। केंद्रीय योजना खेलो इंडिया के साथ समन्वय से राज्य में 52 से 55 के लगभग Khelo India Centres (KICs), KISCE तथा राज्य स्तरीय अकादमियाँ (एथलेटिक्स, शूटिंग, हॉकी, मार्शल आर्ट आदि) विकसित हुईं। जिला स्तर पर सैकड़ों मिनी स्टेडियम, इनडोर हॉल तथा सिंथेटिक ट्रैक बने। तथापि, पूर्ण क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की कमी, ग्रामीण - शहरी तथा आदिवासी क्षेत्रों में असमानता, शिक्षक रिक्तियाँ, उपकरणों की कमी तथा प्रभावी निगरानी की कमी प्रमुख चुनौतियाँ बनी रहीं। अध्ययन सुझाव देता है कि नीति का डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए, NEP-2000 के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए तथा ग्रामीण / आदिवासी स्कूलों के लिए विशेष बजट प्रावधान किया जाए।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 07-04-2026
- **Accepted:** 16-06-2026
- **Published:** 23-06-2026
- **IJCRM:**4(6); 2026: 222-224
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

पाण्डेय एसके, मिश्रा एस, पचौरी पी के, श्रीवास्तव एन. मध्यप्रदेश में 2000 के बाद विद्यालयों में नवीन खेल सुविधाओं का विकास: राज्य खेल नीति के क्रियान्वयन का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(6):222-224.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

मुख्य शब्द: मध्यप्रदेश खेल नीति 2005, विद्यालय खेल सुविधाएँ, खेलो इंडिया योजना, शारीरिक शिक्षा विकास, खेल अधोसंरचना एवं क्रियान्वयन.

1. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश में खेल विकास की व्यवस्थित यात्रा 1989 की प्रथम राज्य खेल नीति से शुरू हुई, जिसका 1994 में पुनर्मूल्यांकन हुआ। वर्ष 2000 के बाद राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप हुए। राज्य स्तर पर 2005 की खेल नीति ने विद्यालयों को खेल विकास का प्रमुख केंद्र बनाया। राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया योजना (2017 से) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने खेल एवं शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा घोषित किया। NEP-2020 स्पष्ट रूप से कहती है कि खेल शिक्षा विद्यार्थियों के समग्र विकास (शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक) के लिए आवश्यक है। मध्यप्रदेश सरकार ने इन राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों को अपनाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय बढ़ाया। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य 2000 के बाद विद्यालयों में नवीन खेल सुविधाओं खेल मैदान, खेल उपकरण, व्यायाम शिक्षक, मिनी स्टेडियम, इनडोर हॉल तथा राज्य / जिला स्तरीय अकादमियों के विकास का मूल्यांकन करना तथा 2005 की राज्य खेल नीति के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का सर्वेक्षणात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्न हैं - 2005 खेल नीति के प्रमुख प्रावधानों (खेल मैदान अनिवार्यता, व्यायाम शिक्षक नियुक्ति, अनिवार्य खेल पीरियड) का क्रियान्वयन स्तर जानना।

खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में विकसित खेल केंद्रों एवं अकादमियों की संख्या एवं प्रभाव का आकलन करना । ग्रामीण, शहरी एवं आदिवासी क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की उपलब्धता में असमानता का विश्लेषण करना। चुनौतियों की पहचान कर भविष्य के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

यह अध्ययन इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि खेल सुविधाओं का विकास न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता तथा राष्ट्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा देता है।

2. साहित्य समीक्षा

मध्यप्रदेश खेल नीति 2005 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में एक खेल मैदान विकसित करने, 5000+ आबादी वाले गांवों में स्कूलों में व्यायाम शिक्षक 3/7 क तथा ग्रामीण खेलों (कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल आदि) को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया। नीति में खेल मैदान विकास के लिए जिला स्तर पर अनुदान भी रखा गया। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में वर्तमान में लगभग 52-55 Khelo India Centres क्रियाशील हैं, जिनमें विभिन्न खेलों (एथलेटिक्स, हॉकी, जूडो, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि) की ट्रेनिंग दी जा रही है।

राज्य में Khelo India State Centre of Excellence तथा कई Accredited Academies (शूटिंग भोपाल, एथलेटिक्स भोपाल, हॉकी ग्वालियर आदि) कार्यरत हैं। एक महत्वपूर्ण अकादमिक अध्ययन (Mishra - Mehta, 2018) ने मध्यप्रदेश के 198 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों (90 सरकारी, 108 निजी) का सर्वेक्षण किया। अध्ययन में पाया गया कि सुविधाओं में कुल वृद्धि हुई है, किंतु ग्रामीण स्कूलों में खेल मैदान, उपकरण तथा शिक्षकों की कमी बनी हुई है। हालिया बजट रिपोर्ट (2025-26) के अनुसार खेल अधोसंरचना पर रू0 643.97 करोड़ व्यय प्रस्तावित था, जिसमें 24 निर्माण पूर्ण, 17 निर्माणाधीन तथा 31वी परियोजनाएँ शामिल थीं। 2026-27 बजट में खेल क्षेत्र के लिए कुल रू. 815 करोड़ (जिसमें खेलो इंडिया डच के अंतर्गत रू0 230 करोड़) आवंटित किए गए हैं। इन रिपोर्टों से स्पष्ट है कि बजट बढ़ा है, किंतु क्रियान्वयन की गति ग्रामीण एवं आदिवासी जिलों (जैसे शहडोल, जबलपुर, अलिराजपुर आदि) में अपेक्षा धीमी रही है।

3. शोध पद्धति

अध्ययन का प्रकार: सर्वेक्षणात्मक (Descriptive Survey based on Secondary Data)

- डेटा संग्रह के स्रोत : मध्यप्रदेश खेल एवं युवा कल्याण विभाग की आधिकारिक
- वेबसाइट (dsywmp.gov.in) तथा वार्षिक रिपोर्ट ।
- 2005 राज्य खेल नीति का मूल दस्तावेज ।
- राज्य बजट दस्तावेज 2025-26 एवं 2026-27 ।
- खेलो इंडिया डैशबोर्ड रिपोर्ट तथा Khelo India Operational Guidelines |
- Samagra Shiksha अभियान के दिशा-निर्देश ।
- पूर्व अकादमिक अध्ययन (Mishra-Mehta, 2018) |

नमूना: पूरे राज्य के 50 जिलों से उपलब्ध जिला एवं राज्य स्तरीय द्वितीयक डेटा (KICS की संख्या, बजट आवंटन, निर्माण कार्य, शिक्षक नियुक्ति आदि) ।

विश्लेषण विधि: गुणात्मक विश्लेषण-नीति प्रावधानों की तुलना वास्तविक क्रियान्वयन से।

मात्रात्मक विश्लेषण - बजट आवंटन, केंद्रों की संख्या, निर्माण कार्यो की प्रगति, ग्रामीण शहरी अनुपात आदि का प्रतिशत एवं प्रवृत्ति विश्लेषण ।

डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए केवल सरकारी एवं प्रकाशित स्रोतों का उपयोग किया गया।

विश्लेषण एवं परिणाम (Data Analysis & Results)

नीति क्रियान्वयन: 2005 नीति के अनुसार 5000+ आबादी वाले 381 गांवों में स्कूलों में व्यायाम शिक्षक नियुक्ति तथा खेल मैदान निर्माण का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में राज्य में सैकड़ों मिनी स्टेडियम, इनडोर हॉल तथा सिंथेटिक ट्रैक विकसित हुए हैं, विशेषकर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर आदि शहरी क्षेत्रों में।

खेलो इंडिया का योगदान: 2017 के बाद मध्यप्रदेश में 52+ Khelo India Centres संचालित हैं। 114 से अधिक Khelo India Athletes चिन्हित हुए। स्कूल स्तर पर Khelo MP Youth Games तथा टैलेंट सर्च कैंप नियमित रूप से आयोजित हो रहे हैं।

समस्याएँ:

ग्रामीण एवं आदिवासी स्कूलों में उपकरणों की कमी, व्यायाम शिक्षकों की रिक्तियाँ (कई स्थानों पर 30-40% रिक्त) तथा नियमित निगरानी की कमी बनी हुई है। 2005 नीति स्वयं पूर्व नीतियों के सीमित क्रियान्वयन को स्वीकार करती है।

सकारात्मक विकास: 2026-27 बजट में खेल क्षेत्र के लिए बढ़ा हुआ आवंटन तथा राज्य स्तरीय अकादमियाँ (शूटिंग, एथलेटिक्स, हॉकी, वॉटर स्पोर्ट्स 5/7 स् प्रतिभाओं को राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जा

रही हैं। Khelo MP Games 2020 (जनवरी 10 से) सभी 313 विकास खंडों में आयोजित होने जा रहे हैं, जो स्कूल स्तर पर खेल संस्तुति को मजबूत करेंगे।

4. चर्चा

नीति का क्रियान्वयन आंशिक रूप से सफल रहा है। शहरी क्षेत्रों में सुविधाएँ अपेक्षा बेहतर हैं, जबकि आदिवासी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आधारभूत ढांचे की कमी है। खेलो इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण किया, किंतु राज्य नीति को स्थानीय आवश्यकताओं (विशेषकर आदिवासी खेलों जैसे मल्लखंब, कबड्डी) के अनुरूप और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बजट वृद्धि सकारात्मक है, लेकिन उपयोग दर तथा गुणवत्ता निगरानी पर ध्यान देने की जरूरत है।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव

2000 के बाद मध्यप्रदेश के विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास सकारात्मक नीति का क्रियान्वयन आंशिक रूप से सफल रहा है। शहरी क्षेत्रों में सुविधाएँ अपेक्षा बेहतर हैं, जबकि आदिवासी एवं दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आधारभूत ढांचे की कमी है। खेलो इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण किया, किंतु राज्य नीति को स्थानीय आवश्यकताओं (विशेषकर आदिवासी खेलों जैसे मल्लखंब, कबड्डी) के अनुरूप और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बजट वृद्धि सकारात्मक है, लेकिन उपयोग दर तथा गुणवत्ता निगरानी पर ध्यान देने की जरूरत है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

दिशा में हुआ है। 2005 खेल नीति तथा खेलो इंडिया योजना ने स्कूल स्तर पर खेल को बढ़ावा दिया, जिससे विद्यार्थियों के शारीरिक एवं समग्र विकास में योगदान हुआ। तथापि, पूर्ण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्न सुझाव दिए जाते हैं - डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम (GIS आधारित) विकसित कर प्रत्येक स्कूल की खेल सुविधाओं का रीयल-टाइम ट्रैकिंग ।

ग्रामीण एवं आदिवासी स्कूलों के लिए विशेष बजट प्रावधान तथा शिक्षक भर्ती अभियान ।
NEP-2020 के साथ पूर्ण समन्वय कर खेल को पाठ्यक्रम का अनिवार्य एवं मूल्यांकित हिस्सा बनाना।
नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रम व्यायाम शिक्षकों के लिए।
भविष्य के अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा (स्कूल सर्वेक्षण) पर आधारित शोध की आवश्यकता।
इस प्रकार निरंतर प्रयासों से मध्यप्रदेश को एक खेल-समृद्ध राज्य बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. Government of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh Sports Policy 2005. Sports & Youth Welfare Department, MP. Available from: https://www.indianemployees.com/acts-rules/details/madhya-pradesh-sports-policy-%E2%80%93-2005
2. Directorate of Sports & Youth Welfare, Madhya Pradesh. Official Website: Sports and Youth Welfare Department. Government of Madhya Pradesh. Available from: https://dsywmp.gov.in/
3. Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India. Khelo India – National Programme for Development of Sports: Scheme Guidelines and Reports. Available from: https://yas.gov.in/en/sports/khelo-india-national-programme-development-sports-0
4. Government of Madhya Pradesh. Budget Documents 2025–26 and 2026–27. Finance Department, Madhya Pradesh.
5. Ignited Minds Journal. An Analysis on the Growth of Physical Education Facilities. 2018. Available from: https://ignited.in

Creative Commons License
This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Author

	संजीव कुमार पाण्डेय अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश में शारीरिक शिक्षा विषय से संबद्ध शोधार्थी हैं। वे खेल शिक्षा, स्वास्थ्य संवर्धन तथा शारीरिक दक्षता से जुड़े विषयों पर अध्ययन एवं अनुसंधान में सक्रिय हैं। उनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शोध के माध्यम से शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक योगदान देना है।
	डॉ. संजीव मिश्रा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश के शारीरिक शिक्षा विभाग में सहायक प्राध्यापक हैं। वे शिक्षण, अनुसंधान तथा अकादमिक मार्गदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनकी रुचि खेल विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा तथा नवाचार आधारित अनुसंधान में है, जिसके माध्यम से वे विद्यार्थियों और समाज को लाभान्वित कर रहे हैं।
	प्रोफेसर (डॉ.) पवन कुमार पचौरी कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में शारीरिक शिक्षा एवं योग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। वे शिक्षण, योग एवं खेल विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय शिक्षाविद् हैं। उनका कार्य विद्यार्थियों के समग्र विकास, स्वास्थ्य जागरूकता तथा अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
	डॉ. नीलम श्रीवास्तव वैष्णवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, रीवा, मध्यप्रदेश की प्राचार्या हैं। वे शिक्षक शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार आधारित शिक्षण तथा भावी शिक्षकों के व्यावसायिक एवं नैतिक विकास को प्रोत्साहित करना है।